क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 02 अंक: 17, शनिवार, 09 फरवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कांग्रेस के 55 साल सत्ताभोग के, भाजपा सरकार के 55 महीने सेवाभाव के: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव में नयी पीढ़ी, खासकर पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवा मतदाताओं की अहम भूमिका का जिक्र करते हुये कहा कि इस चुनाव में युवा पीढ़ी राष्ट्र को नयी दिशा देने में मददगार साबित होगी

नई दिल्ली।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली विभिन्न सरकारों के 55 साल के शासनकाल को ''सत्ताभोग के वर्ष'' और अपनी सरकार के 55 महीने के कार्यकाल को ''सेवाभाव के साल'' करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राफेल विमान सौदे, रोजगार सृजन और भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा बनाये जाने वाले गठबंधनों को 'महामिलावट' बताते हुए अतीत में इस तरह के प्रयोगों के बहुत सफल नहीं रहने का दावा किया। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार को 55 महीनों में आवास, सिंचाई, रक्षा, स्वच्छता आदि क्षेत्रों में वे काम करने पड़े जो आजादी के बाद

अगले दो दशकों में हो जाने चाहिए थे। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा कि देश में आपातकाल लगाने वाले, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने वाले, न्यायपालिका, सेना व जांच एजेंसी का अपमान करने वालों के मुंह से उनके (मोदी) ऊपर संस्थानों को खत्म करने के आरोप शोभा नहीं देते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए बृहस्पतिवार को मोदी ने आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों के महागठबंधन के प्रयासों को 'महामिलावट' की संज्ञा दी। मोदी ने कहा कि देश ने यह महामिलावट 30 साल देखी है। स्वस्थ समाज महामिलावट से दूर रहता है और मजबूत लोकतंत्र में भरोसा करता है। ''महामिलावट अब चलने वाली नहीं है। देशवासी जनता के प्रति समर्पित सरकार चाहते हैं।'' उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस की विभिन्न सरकारों के शासनकाल के 55 साल सत्ताभोग वाले थे जबकि भाजपा की सरकार के 55 महीने सेवाभाव वाले साल रहे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की पहचान पारदर्शिता, ईमानदारी तथा भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने, जनता के लिये तेज गति से काम करने के रूप में बनी है। उन्होंने उज्ज्वला, सौभाग्य योजना, मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया आदि विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका लक्ष्य देश की गरीब जनता का स्तर ऊंचा उठाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए कानून बनाया। उन्होंने इस विधेयक का समर्थन देने के लिए सभी राजनीतिक दलों का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने राफेल सौदे पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में सेना को निहत्था बनाकर रखा और वह नहीं चाहती कि देश की वायुसेना मजबूत हो। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस किसके फायदे के लिये राफेल सौदा रद्द कराना चाहती है? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ''आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से (उनकी संभावित सरकार के खिलाफ) अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे पास समर्पण भाव है इसलिये दो सीटों से यहां तक पहुंच गए और अभिमान के कारण आप (कांग्रेस) 44 रह गए।

ममता बनर्जी के सत्ता में रहने तक बंगाल में नहीं आया कोई नया उद्योग: शिवराज

कोलकाता। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब तक वह सत्ता में हैं राज्य में कोई नया उद्योग नहीं आएगा। चौहान ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुर्गापुर की रैली में गत दो फरवरी को कहे गए शब्दों को दोहराते हुए कहा, ''तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल तोलाबाजी टैक्स (तीन टी) लगाया है। क्या उद्योग आएंगे?'' स्थानीय भाषा में 'तोलाबाजी' को मोटे तौर पर संगठित उगाही समझा जाता है। चौहान ने कहा, ''तीन टी में चौथा टी भी जोड़ दीजिये, वह है ममता बनर्जी (सरकार) का 'टेरर' (खौफ)।'' मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही चार बंगाल वैश्विक व्यापार सम्मेलन (बीजीबीएस) आयोजित कर चुकी है और उन्हें बताया गया कि उद्योग प्रमुखों द्वारा 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने के वादे किये गए।

ब्याज दरों में कटौती से वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, कर्ज सस्ता होगा: वित्त मंत्री

नई दिल्ली। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और छोटे कारोबारियों तथा घर खरीदारों को सस्ता कर्ज उपलब्ध हो सकेगा। रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को चालू वित्त वर्ष की अंतिम द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को चौथाई प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से ब्याज दरें नीचे आएंगी। गोयल ने ट्वीट किया, ''रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत करने और रुख को बदलकर 'तटस्थ' करने के फैसले से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे छोटे कारोबारियों, घर खरीदारों को सस्ता कर्ज उपलब्ध हो सकेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।'' रिजर्व बैंक के फैसले का स्वागत करते हुए आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि यह काफी संतुलित और अग्रसारी नीतिगत समीक्षा है। गर्ग ने ट्वीट किया, ''वृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन वास्तविकता के करीब है।'' उन्होंने रिजर्व बैंक द्वारा अपने रुख को बदलकर तटस्थ करने और रेपो दर में चौथाई प्रतिशत की कटौती के फैसले का स्वागत किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में चौथाई प्रतिशत की कटौती का स्वागत करते हुए कहा कि इससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और निवेशकों की धारणा में सुधार होगा।

तेजस्वी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी आवास खाली करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया और उन्हें विपक्ष के नेता के लिए बने आवास में जाकर रहने का आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता यादव ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।

तीन तलाक विधेयक वापस लेने के वादे पर जेटली ने की कांग्रेस की आलोचना

नई दिल्ली।

तीन तलाक विधेयक वापस लेने के वादे को लेकर कांग्रेस की आलोचना करते हुए केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि लोगों के जमीर को झकझोरने वाली बरेली की 'निकाह हलाला' जैसी घटनाओं को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाना चाहिए। खबरों के मुताबिक, बरेली में एक महिला को उसके पति ने दो बार तलाक दिया और फिर से उससे विवाह किया। इस दौरान महिला को दो बार निकाह-हलाला और इद्दत की मुद्दत का पालन करना पड़ा। पहले तलाक के बाद महिला का निकाह हलाला उसके ससुर के साथ हुआ जबकि दूसरी बार पति के भाई के साथ। मुसलमानों में तलाक देने के बाद यदि कोई व्यक्ति पत्नी से फिर निकाह करना

चाहती है तो महिला को निकाह-हलाला करना होता है। इसमें महिला को किसी दूसरे पुरूष के साथ निकाह कर, वैवाहिक संबंध बनाने होते हैं, फिर उससे तलाक लेना होता है। उसके बाद उसे इद्दत की मुद्दत पूरा करनी होती है। 'बरेली 'निकाह-हलाला' क्या आपकी जमीर को नहीं झकझोरता?' शीर्षक से फेसबुक पर लिखे एक पोस्ट में जेटली ने लिखा है, ''दुर्भाग्यवश, जब सुबह के अखबार में यह खबर पढ़ कर लोगों का जमीर जागना चाहिए था; अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और उनके साथी अल्पसंख्यक सम्मेलन में तीन तलाक पर सजा का प्रावधान करने वाला विधेयक वापस लेने का वादा कर रहे हैं।'' विधेयक फिलहाल संसद में लंबित है। मंत्री ने कहा कि दिवंगत राजीव गांधी ने शाह बानो मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला पलट कर विधायिका की सबसे बड़ी गलती की। न्यायालय ने उस फैसले में सभी मुसलमान महिलाओं को गुजारा भत्ता का अधिकार दिया था। उन्होंने लिखा है, इसने पति द्वारा छोड़ दी गई महिलाओं को गरीबी और अभाव में ढकेल दिया। अब 32 साल बाद उनका बेटा पीछे धकेलने वाला और एक कदम उठा रहा है। जो ना सिर्फ उनको गरीबी की ओर धकेल रहा है बल्कि ऐसा जीवन जीने को मजबूर कर रहा है।

कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, राममंदिर का निर्माण होगा: योगी आदित्यनाथ

उन्होंने बिहार के लोगों से कहा कि वे कुंभ में जाएं और उत्तर प्रदेश में हुए परिवर्तन की प्रशंसा करें

पूर्णिया (बिहार)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि राममंदिर का निर्माण बिल्कुल ''उसी स्थान'' पर किया जाएगा जहां भगवान का जन्म होना माना जाता है और इस संबंध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। आदित्यनाथ ने यहां बूथ स्तरीय भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी सरकार द्वारा शहरों के नाम बदलने के विवादास्पद कदम के बारे में कहा कि भगवान राम के जन्मस्थान आने वाले तीर्थयात्री अब अयोध्या आते हैं, फैजाबाद जिले नहीं आते और जो चल रहे कुंभ में आते हैं

वे प्रयागराज आते हैं, इलाहाबाद नहीं। आदित्यनाथ भाजपा कार्यकर्ताओं की 'शक्ति केंद्र प्रभारियों' की बैठक में बोल रहे थे जो पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज लोकसभा क्षेत्रों से आये थे। ये सभी सीमांचल क्षेत्र में पड़ते हैं जहां मुस्लिमों की अच्छी संख्या है। उन्होंने कहा, ''आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में काफी कुछ होने वाला है। चिंता नहीं करिये, हमने स्पष्ट कर दिया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का मंदिर बिल्कुल उसी स्थान पर बनेगा। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि बिहार सीता माता का जन्मस्थान है। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव नीत पार्टी ने बिहारी कहलाना शर्म की बात बना दिया था। उन्होंने राज्य के बारे में धारणा धीरे धीरे बदलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की प्रशंसा की। आदित्यनाथ ने कहा कि इसी तरह की धारणा में परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाया गया है और वाराणसी में हाल में आयोजित प्रवासी सम्मेलन में एक आगंतुक ने मुझे बताया कि उन्हें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्हें एक नयी पहचान दिखी है।

लालू ने मुजफ्फरपुर कांड में स्स्र के आदेश पर की नीतीश की कड़ी आलोचना

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले को दिल्ली की पॉक्सो अदालत में स्थानांतरित करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अपने धुर विरोधी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जबर्दस्त आलोचना की है। शीर्ष अदालत बिहार में मुजफ्फरपुर के अलावा 16 आश्रय गृह मामलों के प्रबंधन को लेकर बृहस्पतिवार को राज्य सरकार पर जमकर बरसी और आगाह किया कि उसके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसे मुख्य सचिव को तलब करने पर मजबूर होना पड़ेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार सरकार को दो हफ्ते के भीतर मुजफ्फरपुर मामले के सुगम स्थानांतरण के लिए पूर्ण सहयोग देने का भी निर्देश दिया। चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में सजा काट रहे प्रसाद ने ट्वीट के जरिए बिहार सरकार को हुई शर्मिंदगी पर अपना पक्ष रखा। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने अपने देहाती भोजपुरी बोली में कहा, ÷का हो नीतीश, कुछ शरम बचल बा की नहीं।÷ उनका ट्विटर हैंडल उनके करीबी लोग संभालते हैं। एक अन्य ट्वीट में राजद सुप्रीमो ने कड़वे अंदाज में कहा, ÷बिहार के बलात्कारियों को संरक्षण देने के आदी, चुप ही रहेंगे। चुप्प।÷ प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेता इस यौन उत्पीड़न कांड के आरोपियों के खिलाफ लगे इलजामों पर कुमार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते रहे हैं। यह मामला पिछले साल सामने आया था जब मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस) की सामाजिक ऑडिट रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में रह रही लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न होने की बात बताई गई थी। पिछले साल मई में इस बाबत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और आश्रय गृह का संचालन करने वाले एनजीओ के मालिक ब्रजेश ठाकुर समेत कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

मुझे नहीं पता कि मैं भारत रत्न सम्मान का कितना हकदार हूं: प्रणब

कोलकाता। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह भारत रत्न सम्मान के कितने हकदार हैं। अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में भारत रत्न प्राप्त करने के लिए पुस्तक मेला और साहित्य उत्सव के आयोजकों द्वारा सम्मानित किए जाने पर मुखर्जी ने कहा, ''मुझे नहीं पता कि मैं इस सम्मान का कितना हकदार हूं।'' मुखर्जी को हाल में ही भारत रत्न से सम्मानित किये जाने की घोषणा की गई थी। उनके अलावा समाजसेवी नानाजी देशमुख और गायक एवं संगीतकार भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किये जाने की

घोषणा की गई थी। पुस्तक मेला में तीन दिवसीय साहित्य उत्सव का यहां उद्घाटन करते हुए मुखर्जी ने कहा कि पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग के आंदोलन के कारण ही 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि 48 वर्ष पहले जिन लोगों ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया था उनका एक ही नारा था -- बांग्ला को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले। उपलब्ध साहित्यों के मुताबिक विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा उर्दू थी और उस क्षेत्र के लोग बांग्ला को मातृ भाषा बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। मुखर्जी ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसके बाद अंतत~ 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 83 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को बांग्ला भाषा का सम्मान करना चाहिए जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है।

मायावती को SC ने दिया बड़ा झटका, मूर्तियों पर खर्च किया सारा पैसा लौटाना होगा

नई दिल्ली।

अभी हाल ही में बुआ और भतीजे का गठबंधन उत्तरप्रदेश में बनकर तैयार ही हुआ था की ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ गई है। मायावती पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैं। कोर्ट ने कहा की मायावती को मूर्तियों और हाथियों पर लगाया सारा पैसा वापस करना होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि यह अस्थायी आदेश है कि मायावती को लखनऊ और नोएडा में अपनी और पार्टी के चुनाव चिह्न हाथी की मूर्तियां बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए जनता के पैसों को सरकारी खजाने में लौटाना होगा। लखनऊ और नोएडा में लगी हाथी

की मूर्तियों के मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मायावती के वकील को कहा कि अपने क्लाईंट को बता दीजिए की उन्हें मूर्तियों पर खर्च पैसे को सरकारी खजाने में वापस जमा कराना चाहिए। CJI ने कहा कि हमारा प्रारंभिक विचार है कि मैडम मायावती को मूर्तियों का सारा पैसा अपनी जेब से सरकारी खजाने को भुगतान करना चाहिए। मायावती की ओर से सतीश मिश्रा ने कहा कि इस केस की सुनवाई मई के बाद हो, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कुछ और कहने के लिए मजबूर न करें। अब इस मामले में 2 अप्रैल को सुनवाई होगी।

ओवैसी ने की पाकिस्तान की पैरवी, सुषमा ने कराया मुंह बंद

नई दिल्ली। विदेश सुषमा स्वराज ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय अलग-थलग पड़ गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आए प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गले मिले, लेकिन ट्रंप ने साथ छोड़ दिया। सरकार पर विदेश नीति में विफल रहने और भारत के अलग-थलग पड़ जाने का आरोप लगाया तो चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि ओवैसी ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय अलग-थलग पड़ा है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ओर से पाकिस्तान के विरूद्ध जो कार्रवाई हई वो बडी कामयाबी है।

वाड्रा या चिदंबरम किसी की भी जांच कराओ, लेकिन 'राफेल घोटाले' पर कार्रवाई करो: राहुल

नई दिल्ली।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार रॉबर्ट वाड्रा, पी चिदंबरम या किसी के भी खिलाफ जांच कराए, लेकिन 'राफेल घोटाले' पर प्रधानमंत्री जवाब दें और कार्रवाई करें। गांधी ने अंग्रेजी के प्रतिष्ठित अखबार 'द हिंदू' की एक खबर की पृष्ठभूमि में यह भी आरोप लगाया कि इस विमान सौदे को लेकर मोदी ने फ्रांस के साथ

समानांतर बातचीत कर रक्षा मंत्रालय के पक्ष को कमजोर किया और पूरी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए अपने 'मित्र' अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपये का कांट्रैक्ट दिलवाया। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, ''हम यह एक साल से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राफेल घोटाले में सीधे तौर पर शामिल हैं। अखबार की रिपोर्ट से साफ है कि प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ समानांतर बातचीत कर रहे थे। मैं देश के युवाओं और रक्षा बलों से कहना चाहता हूं कि अब स्पष्ट हो चुका है कि प्रधानमंत्री ने प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए आपके 30 हजार करोड़ रुपये चुराए और अपने मित्र अनिल अंबानी को दे दिए। इसकी जांच होनी चाहिए।'' गांधी ने कहा, '' पहले फ्रांस्वा ओलांद (फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति) ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बोला था कि अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपये का अनुबंध दिया जाए। अब रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने चोरी की है। पूरा मामला एकदम स्पष्ट है।' उन्होंने कहा, ''वायुसेना के मेरे पायलट मित्रों, आप लोग समझ लो कि ये 30 हजार करोड़ रुपये आपके लिए इस्तेमाल हो सकते थे । उन्होंने ये पैसे अनिल अंबानी को दे दिए। अब साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री ने इस देश से चोरी की है। मैं कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन करने को विवश हो रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री चोर हैं।'' गौरतलब है कि अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर आपत्ति जताई कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने राफेल विमान सौदे को लेकर फ्रांस के साथ समानांतर बातचीत की जिससे इस बातचीत में रक्षा मंत्रालय का पक्ष कमजोर हुआ। राफेल विमान सौदे को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी प्रधानमंत्री और अनिल अंबानी पर लगातार हमले कर रहे हैं। सरकार और अनिल अंबानी के समूह ने उनके आरोपों को पहले ही खारिज किया है। रॉबर्ट वाड्रा से धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर भाजपा के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, '' जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हो करो क्योंकि आप सरकार में हो, लेकिन इस पर (राफेल) भी कार्रवाई करो।

संपादकीय

52 दिन में वचन पत्र के 26 बिंदु पूरे

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कमल नाथ सरकार वर्किंग मोड पर आ गई।अल्प समय में कमल नाथ सरकार ने जनहित के अनेक फैसले लिये। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश,नया आध्यात्म विभाग समेत ताप्ती, मंदाकिनी और क्षिप्रा नदी न्यास गठित करने का फैसला लिया। वचन पत्र के मुताबिक किसानों को दिए जाने वाले 2 लाख रुपए मूल्य तक के कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत का अनुदान देने का आदेश जारी किया। वचन पत्र के अनुसार गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने का वादा पूरा कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने अपने 52 दिन के कार्यकाल में वचन पत्र में जनता से किए गए 26 वचनों की पूर्ति करके बता दिया कि जनहित और प्रदेश हित सरकार का लक्ष्य होगा। शपथ लेने के 2 घंटे बाद ही प्रदेश के 55 लाख किसानों के 50 हजार करोड़ के ऋण माफ करने का निर्णय लेकर वचन पत्र का पहला वचन पूरा किया गया। यही नहीं उन्होंने मुख्य सचिव को वचन पत्र सौंपकर मंशा जताई कि अगले पांच साल का मुख्य एजेंडा यही है, इसे पूरा करना होगा।

पहले दिन से ही वर्किंग मोड पर: 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कमल नाथ सरकार वर्किंग मोड पर आ गई और उन्होंने अपनी सरकार के काम करने की तेज गति को बताया। किसानों के बाद युवाओं को रोजगार देने के वचन पत्र के दूसरे बिन्दु को पूरा करने के लिए निर्णय लिया गया कि अब उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के स्थानीय लोगों को देना जरूरी होगा। प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करने और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए मोहना, धार, भोपाल, छिंदवाड़ा और जावरा में टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना का फैसला किया। युवा स्वाभिमान योजना के जरिए युवाओं को 100 दिन का काम उपलब्ध कराने के साथ साथ कौशल विकास के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

वचन पत्र के तीसरे बिन्दु कन्या विवाह निकाह योजना का अनुदान 28 से बढ़ाकर 51 हजार रुपए करने का निर्णय लिया। वृद्धावस्था तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 600 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। दिव्यांग महिला और सामान्य पुरुष के बीच विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई।

पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश: आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिन रात लगे रहने वाले पुलिस कर्मियों के हित में पुलिस बल को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देने का फैसला लागू हो गया है। पुलिस बल में 50 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती और उनका आवास भत्ता बढ़ाने का भी प्रस्ताव प्रक्रिया में है।

नया आध्यात्म विभाग गठित: वचन पत्र के एक और बिन्दु को पूरा करते हुए सर्वधर्म समभाव बढ़ाने के लिए नया आध्यात्म विभाग गठित किया। ताप्ती, मंदाकिनी और क्षिप्रा नदी न्यास भी गठित करने का फैसला लिया। मंदिरों के पुजारियों को वेतन 1500 से बढ़ाकर 3 हजार रुपए करने के बाद ही प्रदेश में 1000 गौ शालाएं निराश्रित गायों के लिए खोलने का निर्णय लिया। इससे प्रदेश की एक लाख निराश्रित गायों को आसरा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 3600 लोगों को इलाहाबाद में हो रहे कुंभ में भेजने का फैसला लिया। इसके लिए 12 फरवरी, 14 फरवरी, 22 फरवरी एवं 24 फरवरी को विशेष ट्रेन रवाना होगी। वंदे मातरम को नए सिरे से भव्य स्वरूप में शुरू कर लोगों में देश भक्ति की एक नई भावना का संचार दिया गया।

अल्प समय में जनहित के अनेक फैसले: अल्प समय में कमल नाथ सरकार ने जनहित के अनेक फैसले लिये। शासकीय विद्यालयों में 52 रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की। मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार पर सख्ती से रोक लगाने, आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और बिजली की सतत सुचारू आपूर्ति के लिए खराब ट्रांसफार्मर तत्काल बदलने के निर्देश दिए। ग्रामीण परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के साथ ही प्रत्येक हल्के पर पटवारी पदस्थ करने को कहा।

कृषक हित संबंधी अनेक फैसले: वचन पत्र के मुताबिक किसानों को दिए जाने वाले 2 लाख रुपए मूल्य तक के कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत का अनुदान देने का आदेश जारी किया। आधुनिक तकनीक से सब्जियों, फसलों, औषधियों और फूल उगाने वाले उत्पादको के पॉली हाउस और ग्रीन हाउसों का आकार 1000 से 5000 हजार वर्ग फिट तय किया गया। इसके लिए उनको ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसानों को दस हार्स पावर तक पंपों के लिए आधी दरों पर बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है। सभी घरों में 100 यूनिट तक की बिजली खपत पर 100 रुपए का बिल आए, इसकी तैयारी की जा रही है। वचन पत्र के एक और बिन्दु के जरिए आधुनिक तकनीक से मृदा और बीज के परीक्षण की सुविधा किसानों को दी गई। खरबूज, तरबूज, सिंघाड़े और कमल ककड़ी की खेती को फसल कार्यक्रम में शामिल कर उन्नत बीज बाजार एवं अनुदान देने के आदेश भी जारी हो गए हैं। वचन पत्र के अनुसार गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने का वादा पूरा कर दिया गया है।

बिजली बिल सुधार और प्रदाय संबंधी फैसले: इसी तरह बिजली सप्लाई, ट्रांसफार्मर की बिजली फेल होने और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गलत बिजली बिल बनने की शिकायतों के लिए कॉल सेंटर बनाए गए हैं। शिकायत 1912 पर दर्ज करवाई जा सकती है। समय सीमा में इनका निराकरण हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। ये कॉल सेंटर 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दों के निराकरण के लिए एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के एचआर हेड की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। घाटे में चल रहे मध्यप्रदेश पर्यटन निगम के होटलों को निजी क्षेत्र में देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दस होटल 30 साल की लीज पर दिए जा चुके हैं और 11 होटलों का चयन भी कर लिया गया है। वचन पत्र के मुताबिक 10 हेरीटेज भवन को निजी क्षेत्र में देने के लिए चिन्हित किया गया है। भोपाल स्थित मिंटो हॉल को हेरीटेज कन्वेंशन में बदला गया है।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन: वचन पत्र के मुताबिक राज्य स्तरीय मैडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कोचिंग और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी के लिए सभी तरह का सहयोग प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भविष्य में सभी खेल प्रतियोगिताओं में महिला खिलाड़ियों के साथ महिला खेल अधिकारी या महिला कोच को भेजा जाना अनिवार्य किया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जिला खेल अधिकारी का नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये खेल विभाग के अतिरिक्त पदेन निदेशक होंगे। ग्राम सभाओं में महिलाओं की विशेष भागीदारी के लिए 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबला महिला सभा और 19 नवंबर को प्रियदर्शनी महिला सभा की जाएगी। प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को सम्मान देने के उद्देश्य से बादल भोई और जनगण श्याम के नाम पर पुरस्कार स्थापित किए गए। अनुसूचित जनजाति के युवाओं के कौशल विकास के लिए जिला स्तर पर कोचिंग सेंटर खोले गए। चिन्हित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को मजबूत बनाया गया है। उपभोक्ताओं के लिए एफपीएस युक्त 30 गोदाम का निर्माण और बेहतर निगरानी के लिए आईटी सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल बीआरटीएस की मौजूदा स्थिति के आकलन और संभावित सुधार के लिए मेनिट को नियुक्त किया गया है। फिलहाल बीसीएलएल द्वारा स्कूल बसों को बीआरटीएस ट्रैक पर कुछ शर्तों के साथ चलाने की इजाजत दी गई है।

रियायती दर पर दाल वितरण: कमल नाथ सरकार ने उचित मूल्य की 24 हजार से अधिक दुकानों से 1 लाख 17 हजार पात्र परिवारों को रियायती दर पर प्रतिमाह चार किलो दाल वितरण की शुरुआत की। गुमाश्ता कानून में नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दस लाख से अधिक छोटे व्यावसायियों को लाभांवित किया। सभी नगरीय निकायों को शव वाहन उपलब्ध कराने का फैसला भी सरकार ने लिया।

■ **मनोज पाठक**

(लेखक मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी है)

विचार

आरबीआई से मिली सौगात

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर दी है। इस निर्णय से होम और ऑटो लोन वाले ग्राहकों को फायदा होगा। सरकार भी आरबीआई से रेपो रेट में कटौती की उम्मीद लगाए थी। अब इस निर्णय ने सरकार के काम पर भी मुहर लगा दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल दिसंबर माह में समीक्षा के दौरान ब्याज दरों में कोई कटौती तो नहीं की थी, लेकिन यह आश्वासन दिया था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से आए आंकड़ों ने यह साफ किया था कि दिसंबर में थोक महंगाई की दर 2.19 फीसदी रही थी जो पिछले डेढ़ वर्षों का न्यूनतम स्तर था। इस आंकड़े के बाद से ही कहा जाने लगा था कि रिर्जव बैंक ब्याज दरों के प्रति नरमी का रुख रखेगा। पिछली कई मौद्रिक समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने महंगाई का हवाला देकर रेपो रेट में कटौती की संभावना को नकार दिया था। अब इस बार जब रेपो रेट में कटौती कर दी गई है, तो यह आम लोगों के राहत की बड़ी खबर है। इसके बाद होम लोन के साथ ही ऑटो लोन की ब्याज दरें कम हो सकती हैं। रेपो रेट को 6.50 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी किया गया है, यानी इसमें 25 आधार अंकों की कटौती की गई है। रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। कमी होने से बैंकों को कम ब्याज देना होता है।

रिजर्व बैंक के निर्णय का सबसे बड़ा फायदा होम लोन रेट में कटौती का होगा। होम लोन रेट में 25 बेसिस अंक की कटौती से 20 साल की समय सीमा वाले 10 लाख रुपए के लोन पर ईएमआई में प्रतिमाह करीब 168.40 रुपयों की कमी आ सकती है। फिर उपभोक्ताओं के ज्यादा खर्च के साथ ही कॉर्पोरेट्स और कन्जयूमर्स के लिए लोन की सुलभता की वजह से आर्थिक विकास दर तेज होने की संभावना है। ऐसा होने पर रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। मार्केट के बदले माहौल में कंपनियां इक्विटी बढ़ा सकेंगी, सरकार के विनिवेश की प्रक्रिया की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। भाजपा ने वर्ष 2014 के अपने चुनावी घोषणा में यह वादा किया था कि वह होम लोन एवं अन्य कर्जे की दरों को कम करेगी। वहीं स्टेट बैंक की आर्थिक शोध इकाई ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया था कि आरबीआई ब्याज दरों को घटाने के लिए रेपो रेट में 0.25 की कटौती कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स भी कह चुकी है कि कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और महंगाई की दर में भारी गिरावट को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश बनती है।

ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई थी कि अभी महंगाई में कुछ और वृद्धि होगी, तब भी यह आरबीआई के लक्ष्य से नीचे ही रहेगी। बहरहाल, अब बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे ग्राहकों को शीघ्र ब्याज दरों को कम होने का फायदा दें। यह मुद्दा अभी कुछ दिनों पहले ही उठा था कि जब आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है, तो बैंक तत्काल ब्याज दरें बढ़ा देते हैं और जब रेपो रेट कम होती है तब बैंक फायदा देने में देर लगाते हैं या फिर आधा–अधूरा लाभ देते हैं। रेपो रेट कम करने के बाद यह आरबीआई के लिए चुनौती भरा काम है कि ग्राहकों को पूरा लाभ मिल सके।

यातायात की समझ विकसित नहीं

नियम, कायदे व कानून हम सभी की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इनका पालन सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर कब तक हमें पुलिस या फिर बुद्धिजीवी समझाइश देते रहेंगे। हमें खुद अपनी व अपने परिवार की चिंता करनी होगी। यह तभी हो सकेगा, जब हम सड़क सुरक्षा संबंधी यातायात के नियमों का पूरी तरह पालन करेंगे। इन नियमों को बोझ समझकर अनदेखी करना बेहद घातक सिद्ध हो सकता है। सड़क हादसे में होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए दूसरों को नहीं खुद को बदलकर जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। सड़क पर चलने के कई नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। इसी प्रकार जाने-अनजाने कई गलतियां भी सड़क पर होती हैं, उन्हें भी दूर करना होगा। इसमें एक है सड़क पर रैली, धरना-प्रदर्शन, बारात व धार्मिक यात्रा निकालना आदि। इसके पीछे का कारण यह है कि आए दिन इस तरह की गतिविधियों के होने से बीमार, गंभीर घायल या किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकला कोई व्यक्ति अनायास ही भीड़-भाड़ और जाम में फंस जाता है। यहां तक कि बीमार व गंभीर घायल व्यक्ति समय से इलाज न होने के कारण जान गवां देता है।

सड़क पर बहुत कुछ नहीं होना चाहिए। उनमें से एक है होर्डिंग। देखने में आता है कि चौराहा हो या मोड़, जगह-जगह होर्डिंग रखने की होड़-सी हो चली है। इसके कारण विजिबिलिटी नहीं होती और वाहनों के एक-दूसरे से टकराने का भय हमेश बना रहता है। इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार कर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही चौराहे पर लगे होर्डिंग से सिग्नल नहीं दिखते, इससे भी दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। जहां दोपहिया वाहनों पर ओवर लोडिंग और मोबाइल पर बात करना दुर्घटना को आमंत्रित करता है। वहीं चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाने से दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु तक से बचा जा सकता है। सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों में से एक शराब पीकर वाहन चलाना भी है। जरूरी है कि लंबी दूरी की सड़क यात्रा से बचा जाए अत्यंत आवश्यक होने पर ही यह यात्रा की जाना चाहिए।

प्रायः देखने में यह आता है कि नागरिक लंबी दूरी की यात्रा के समय ड्रायवर का सहारा लेते हैं और लंबे समय लगातार बिना रुके वाहन चलवाते हैं। ऐसे समय वाहन चालक को आराम देने की जरूरत है। रात के समय तो सफर करने से बचना ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिकांश दुर्घटनाएं वाहन चालक को नींद का झोंका आने के कारण होती पाई गई हैं। अधिकतम 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा वाहनों की गति नहीं रखने में ही समझदारी है। अत्यधिक बारिश, कोहरा और खराब मौसम होने की स्थिति में सड़क मार्ग के जरिए यात्रा से बचा जाना चाहिए। कभी-कभी ओवर टेक करना भी मृत्यु का कारण बनता है। इससे बचने के लिए वाहन चालक को धैर्य रखना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसी प्रकार ट्रैक्टर-ट्राली वालों के लिए एक अभियान चलाकर उनके ट्रालों के पीछे रेडियम प्लेट लगाने की आवश्यकता है। इससे रात में विजिबिलिटी बनने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसी प्रकार अधिकतर देखने में आता है कि हाई-वे पर पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक गलत दिशा में वाहन चलाकर एक दम से बड़े वाहनों के सामने आकर मृत्यु को आमंत्रित कर लेते हैं।

लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने और सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से 4 से 10 फरवरी तक 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सड़क पर सुरक्षा का काम हर दिन करना होगा। ऐसा तभी हो सकेगा, जब लोग खुद से जागरूक होंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे।

लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने और सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से 4 से 10 फरवरी तक 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सभी नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ दिनों की बात नहीं है। सड़क पर सुरक्षा का काम हर दिन करना होगा। ऐसा तभी हो सकेगा, जब लोग खुद से जागरूक होंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। आसान है, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कर असामयिक मृत्यु से बचा जा सकता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य भी यही है कि हमारी, आपकी और दूसरों की भी जान बच सके। सरकार सड़क हादसों को रोकने के जो उपाय कर रही है, उसमें सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि लोगों को नियमों की परवाह नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी तेज गति से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना और हेलमेट व सीट बेल्ट न बांधना ऐसी लापरवाही हैं, जो हम रोज करते हैं।

भारत में बढ़ते सड़क हादसे गंभीर चिंता का विषय हैं। देश में रोज होने वाले एक हजार से ज्यादा सड़क हादसों में करीब चार सौ लोग जान गंवा बैठते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सलाना रिपोर्ट के अनुसार हर साल होने वाले औसतन साढ़े चार लाख सड़क हादसों में डेढ़ लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय सड़क संगठन के मुताबिक दुनियाभर में हर साल सड़क दुर्घटनाओं की वजह से 12 लाख लोग मारे जाते हैं और 50 लाख लोग प्रभावित होते हैं। इनमें करीब 12 फीसद हादसे भारत में होते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सर्वाधिक हैं। गौरतलब है कि ऐसे ज्यादातर हादसे यातायात नियमों का पालन नहीं करने, सड़कों की गुणवत्ता खराब होने, तेज गति से वाहन चलाने, थकान और नशे की हालत में वाहन चलाने और नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने और गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारियां भरने के कारण ही हुए हैं। ऐसे जानलेवा हादसों पर अंकुश लगाना इसलिए भी जरूरी है कि इस वजह से मानव संसाधन का व्यापक स्तर पर असमय विनाश हो रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को हर साल 58 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। यह राशि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन फीसद से अधिक बैठती है। यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे यहां जितने लोगों की मौत आतंकी घटनाओं की वजह से होती है, उससे कई गुना ज्यादा मौतों की एकमात्र वजह सड़क हादसे हैं। ऐसे हादसे कई बार लोगों के महत्वपूर्ण अंग छीन लेते हैं। कृत्रिम विकलांगता का यह रूप लोगों को आर्थिक रूप से लाचार तक बना देता है, जबकि किसी परिवार के कमाने वाले एकमात्र सदस्य की सड़क दुर्घटना में मौत से परिवार बेसहारा हो जाता है। रिपोर्ट बताती है कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में 18 से 35 वर्ष के युवाओं की तादाद सर्वाधिक यानी 46 फीसद है। देश की आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी करीबन 65 फीसद है। लेकिन कई युवा अपने वाहन की उच्च गति से समझौता नहीं करना चाहते, जिससे कई बार वाहन पर नियंत्रण नहीं रह जाता और वे हादसे का शिकार हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चालक अगर अपनी रफ्तार में पांच फीसद की भी कमी लाता है, तो जानलेवा दुर्घटना की संभावना को 30 फीसद तक कम किया जा सकता है।

देश में अधिकांश सड़क हादसे सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही, नियमों के उल्लंघन और मानवीय चूक की वजह से होते हैं। हादसों को रोकना भी हमारे हाथों में ही है। सरल यातायात नियमों का सहजता से पालन और चालकों और यात्रियों को जागरूक बना कर सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। जरूरत इसकी है कि लोग यातायात नियमों के प्रति अपनी सच्ची वफादारी निभाना सीख जाएं।

■ **दुर्गेश रायकवार**

(नोडल अधिकारी, राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति)

ट्विटर

रेपो रेट में कमी ने यह साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार की नीतियां सही रास्ते पर हैं। देश में महंगाई को कम करने के प्रयास अब रंग दिखाने लगे हैं।

एसपी शुक्ल, वित्त राज्यमंत्री

रेपो रेट में कमी का श्रेय सरकार लेना बंद करे। सरकार कई दिनों से कह रही है कि महंगाई कम हो गई, पर आरबीआई ने रेपो रेट कम नहीं की। यह फैसला बैंक का है।

यशवंत सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री

सत्यार्थ

जीवन में ऊंचे आदर्श अपनाएं

अपने जीवन काल में 52 ग्रंथों की रचना करने वाले और भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्वावलंबन व सादगी के प्रतीक थे। एक बार विद्यासागर को इंग्लैंड में एक सभा की अध्यक्षता करनी थी। उनके बारे में यह मशहूर था कि उनका प्रत्येक कार्य घड़ी की सुई के साथ पूर्ण होता है। वे लोगों से भी यही अपेक्षा रखते थे कि वे अपना कार्य समय पर करें।

विद्यासागर जी जब निश्चित समय पर सभा भवन पहुंचे तो देखा कि लोग बाहर घूम रहे हैं। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि सफाई कर्मचारियों के न आने की वजह से अभी भवन की सफाई नहीं हुई है। यह सुनते ही विद्यासागरजी ने बिना देर किए झाड़ू उठाई व सफाई शुरू कर दी। उन्हें ऐसा करते देख बाकी लोगों ने भी सफाई करना शुरू कर दी। देखते ही देखते भवन साफ हो गया और सारा फर्नीचर यथास्थान लगा दिया गया। जब सभा आरंभ हुई तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने संबोधन में कहा-कोई व्यक्ति हो अथवा राष्ट्र, उसे स्वावलंबी होना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा कि एक-दो व्यक्तियों के न आने से हम सभी परेशान हो रहे थे। संभव है कि उन लोगों तक इस कार्य की सूचना न पहुंची हो या फिर किसी अन्य वजह से वे यहां न पहुंच सके हों। क्या ऐसी दशा में आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाता? यदि ऐसा होता तो कितने लोगों का आज का श्रम व समय व्यर्थ हो जाता। सार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए और वक्त पड़ने पर किसी भी कार्य को करने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति भी जीवन में उच्च आदर्श अपनाकर किस तरह महानता को प्राप्त करता है, विद्यासागरजी का जीवन हमें यही सिखाता है।

■ **विनोद कुमार यादव**

19 करोड़ लोगों के पैन कार्ड हो जाएंगे रद्द!

नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है। इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च के काफी पास आ जाने के बाद भी अब तक 50 प्रतिशत पैनकार्ड धारकों ने ही अपने आधार को पैन से जोड़ा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किए हैं। इनमें से 23 करोड़ लोगों ने ही पैन से आधार जोड़ा है। आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि पहले 30 जून, 2018 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2019 कर दी गई है अगर आपने तय समय-सीमा के भीतर पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अब आप ऑनलाइन ढ्ढञ्जक्र फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है। साथ ही, कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के लिंक आधार पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। लॉगइन करते ही पेज खुलेगा। ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें। प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। इसे सेलेक्ट करें, यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें। जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें आप एसएमएस बेस् ड सर्विस का इस् तेमाल करते अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं। इनक म टैक स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।

किसानों के लिए बहुत काम का साबित होगा एप, उत्पादकता और आय बढ़ाने में करेगा मदद

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया आधारित इनोवेटिव एग-टेक कंपनी मूफार्म ने मूफार्म एप लांच किया है। यह एप डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने में मदद करता है। एप विभिन्न पहलुओं जैसे दूध, मवेशी, प्रजनन के तरीकों, स्वास्थ्य, उत्पादकता से जुड़े आंकड़ों के आधार पर किसान को सही फैसला लेने में मदद करता है। मूफार्म के संस्थापक परम सिंह ने कहा, यह एप किसान को हर मवेशी के पूरे जीवनचक्र को मानीटर करने में मदद करेगा। इसके अलावा किसान आसानी से अपने डेयरी अकाउन्ट का प्रबंधन कर सकेगा। मूफॉर्म का कॉल सेंटर किसानों को हर जरूरी सहयोग प्रदान करता है साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें इनपुट आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं, ऋण एवं बीमा कंपनियों के साथ भी जोड़ता है। उन्होंने कहा कि यह एप किसानों के लिए स्मार्ट लर्निंग सोल्यूशन लेकर आया है, जिसके द्वारा वे अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे और अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाकर अपना मुनाफा बढ़ा सकेंगे।

यह एप विलेज लेवल एंटरेप्रेन्यूर /वीएलई के नेटवर्क पर आधारित है, कंपनी हर 2-3 गांवों के लिए एक वीएलई नियुक्त करती है जो 100-150 किसानों को कवर करता है। ये वीएलई विशेषज्ञों के साथ किसानों के पास जाते हैं और उन्हें डेयरी की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं पर प्रशिक्षण देते हैं।

देश में दालों की पर्याप्त उपलब्धता, आयात पर रोक लगाए सरकार

इंदौर। देश में दाल-दलहनों की पर्याप्त उपलब्धता का दावा करते हुए उद्योग जगत के एक प्रमुख संगठन ने शुक्रवार को मांग की कि केंद्र सरकार को अगले वित्त वर्ष में दालों के आयात पर रोक लगा देनी चाहिए। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा, मोटे अनुमान के मुताबिक हमें घरेलू उपभोग के लिए हर साल 250 लाख टन दालों की आवश्यकता होती है। देश में अब तक हुए दाल-दलहन उत्पादन, आयात और निजी तथा सरकारी क्षेत्र के पुराने स्टॉक के बूते हम इस आवश्यकता की पूर्ति करने में खुद सक्षम हैं। लिहाजा अगले वित्त वर्ष में दाल आयात पर रोक लगा देनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर दाल के आयात पर रोक लगाई जाती है, तो घरेलू दाल उद्योग के साथ देश के किसानों को भी फायदा होगा। ऐसा होने पर किसानों को दलहनों की वाजिब कीमत मिल सकेगी, जबकि खासकर दाल आयात के कारण अभी उन्हें अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से भी नीचे बेचनी पड़ रही है। अग्रवाल ने यह मांग भी की कि आम उपभोक्ताओं और घरेलू उद्योग के हितों को देखते हुए ब्रांडेड दालों पर पांच फीसदी की दर से वसूला जाने वाला माल एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाया जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत से पहले, उन्होंने यहां औद्योगिक प्रदर्शनी ग्रेनेक्स इंडिया के आठवें संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्णमुरारी मोघे भी मौजूद थे। आयोजकों ने बताया कि तीन दिवसीय कार्यक्रम में कई देशी-विदेशी कम्पनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान दाल उद्योग के करीब 2,000 प्रतिनिधियों के जुटने की उम्मीद है।

आरबीआई के लाभांश के उपयोग का फैसला सरकार करेगी : शक्तिकांत दास

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गर्वनर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को दिए गए अधिशेष और लाभांश के उपयोग के बारे में निर्णय लेना सरकार का विशेषाधिकार है। यह पूछे जाने पर कि राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए आरबीआई के लाभांश के उपयोग के बारे में उनकी क्या राय है। उन्होंने कहा, ÷सरकार आरबीआई के लाभांश या अधिशेष का उपयोग कैसे करती है, यह फैसला उन्हें लेना है।÷ केंद्रीय बैंक के अधिशेष का केंद्र सरकार को हस्तांतरण पिछले आरबीआई गर्वनर उर्जित पटेल और केंद्र सरकार के बीच तनातनी का प्रमुख मुद्दा था, जबकि सरकार का मानना था कि आरबीआई के पास जरूरत से अधिक अधिशेष है। यह पूछे जाने पर क्या सरकार आरबीआई पर दवाब बना रही है कि वह अंतरिम लाभांश के साथ ही पिछले साल का अधिशेष भी सरकार के हवाले कर दे। दास ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह महज अटकलबाजी है और आरबीआई हमेशा कुछ सिद्धांतों और लेखांकन नियमों के हिसाब से चलती है। दास ने अपनी पहली

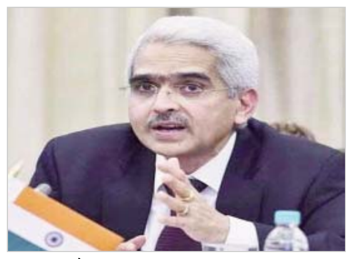

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अध्यक्षता के बाद कहा, आरबीआई द्वारा अधिशेष या लाभांश का भुगतान आरबीआई अधिनियम का हिस्सा है। यह एक कानूनी प्रावधान है और कानूनी प्रावधान में जो कुछ है, उसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर रहे हैं।

छह पैसे लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल के भाव स्थिर

नई दिल्ली। पेट्रोल के दाम में दो दिनों की स्थिरता के बाद शुक्रवार को फिर छह पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है जबकि डीजल के भाव स्थिर रहे। तेल विपणन कंपनियों ने गुरुवार को डीजल के दाम बढ़ा दिए थे। उधर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण कच्चे तेल के दाम में फिर नरमी का रुख बना हुआ है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में शुक्रवार को पेट्रोल के दाम घटकर क्रमशः 70.38 रुपये, 72.49 रुपये, 76.02 रुपये और 73.05 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। चारों महानगरों में डीजल के भाव क्रमशः 65.56 रुपये, 67.34 रुपये, 68.65 रुपये और 69.25 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहे। डीजल के दाम में गुरुवार को दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में पांच पैसे और चेन्नई में छह पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी। अप्रैल डिलीवरी अनुबंध में पिछले सत्र के मुकाबले 0.67 फीसदी की कमजोरी के साथ 61.22 डॉलर बैरल पर कारोबार चल रहा था। वहीं, न्ययॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी नायमैक्स पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी डब्ल्यूटीआई के मार्च सौदे में 0.80 फीसदी की गिरावट के साथ 52.22 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।

वर्ष 2018-19 के लिए कम कपास उत्पादन अनुमान, आयात बढ़ेगा

मुंबई। भारतीय कपास संघ (सीएआई) ने एक अक्तूबर 2018 से शुरु होने वाले कपास वर्ष में कपास उत्पाद के बारे में अपने पिछले अनुमान को पांच लाख गांठ कम कर 330 लाख गांठ (कपास की एक गांठ 170 किग्रा का होता है) कर दिया है। घरेलू उत्पादन में इस कमी से कपास आयात 80 प्रतिशत बढ़ सकता है। सीएआई ने यहां बृहस्पतिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि इससे पूर्व के दिसंबर अनुमान में सीएआई ने कपास उत्पादन 335 लाख गांठ रहने का अनुमान लगाया था। कपास विपणन वर्ष एक अक्ट्रबर 2018 से शुरु होता है। सीएआई के अध्यक्ष अतुल गणत्र ने बताया, ''वर्ष 2009 में कपास उत्पादन सबसे कम यानी 305 लाख गांठ था जबकि वर्ष 2015-16 में यह 332 लाख गांठ था। इस वर्ष यह दूसरा सबसे कम स्तर यानी 330 लाख गांठ रहने का अनुमान है।'' कपास का आयात 12 लाख गांठ अधिक (लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि) यानी 27 लाख गांठ होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष यह आयात 15 लाख गांठ ही थी। सीएआई ने कपास की खपत 316 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है सीएआई ने कपास की खपत 316 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है जो पिछले महीने के अनुमानित खपत के आंकड़े की तुलना में चार लाख गांठ कम है। कपास के उत्पादन में कमी करने का मुख्य कारण प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में कम बरसात का होना बताया गया है। फसल अनुमान में कमी करने का मुख्य कारण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना सहित दक्षिणी क्षेत्रों में किसान मुख्यतः नमी की कमी के बाद बहुत से खेतों को उजाड़ दिया है।

रिकॉर्ड घाटे से टाटा मोटर्स के शेयर धराशायी, 16फीसदी तक लुढ़के

नई दिल्ली। तीसरी तिमाही में हुए रिकॉर्ड घाटे की वजह से शुक्रवार को शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में टाटा मोटर्स के शेयर में 16 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी को 26,961 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। इसकी ब्रिटिश यूनिट जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) के 27,838 करोड़ रुपए के एक बार के इंपेयरमेंट चार्ज, चीन में बिक्री कम होने और ब्रेग्जिट से जुड़ी मुश्किलों के चलते टाटा मोटर्स को किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे बड़ा घाटा हुआ है। कंपनी ने दावा किया कि जेएलआर यूनिट के लिए प्रोजेक्ट चार्ज टर्नअराउंड प्लान के तहत 2.5 अरब डॉलर की बचत का काम ट्रैक पर है। इस प्रोजेक्ट को कुछ महीने पहले शुरू किया गया था। उसने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2019 के लिए ब्रेक-ईवन एबिट (अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज) का गाइडेंस पूरा नहीं होगा। कंपनी का इस वित्त वर्ष में नेगेटिव मार्जिन रह सकता है। टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2020-22 के लिए जेएलआर के लॉन्ग टर्म एबिट गाइडेंस को भी 4-7 पर्सेंट से घटाकर 3.6 फीसदी कर दिया है। एसेट इंपेयरमेंट के लिए वन टाइम के एक्सेप्शनल नॉन-कैश चार्ज से कंपनी के डेप्रिसिएशन और एमॉर्टाइजेशन में 30 करोड़ डॉलर की कमी आएगी। टाटा मोटर्स को लगातार तीन तिमाहियों से घाटा हो रहा है। साल भर पहले की दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 1,214.60 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। टाटा मोटर्स को तीन चौथाई बिक्री जेएलआर से मिलती है। एक एकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बताया, इंपेयरमेंट चार्ज से टाटा मोटर्स की नेटवर्थ कम हो गई है। यह भविष्य में कंपनी के फंड जुटाने की योजना के लिए ठीक नहीं है। इससे पता चलता है कि जेएलआर का परफॉर्मेंस आगे खराब रहेगा। जब आने वाली तिमाहियों में मुनाफे में गिरावट आनी हो तो 30 करोड़ डॉलर की बचत का कोई मतलब नहीं है। टाटा मोटर्स की आमदनी दिसबंर क्वॉर्टर में 5 फीसदी बढ़कर 77,001 करोड़ रुपए हो गई। इसमें करेंसी में उतार-चढ़ाव से कंपनी को फायदा हुआ क्योंकि टाटा मोटर्स और जेएलआर दोनों की बिक्री में गिरावट आई। कंपनी का कंसॉलिडेटेड ऑपरेटिंग मार्जिन 2.3 फीसदी गिरकर 8.5 फीसदी रह गया। टाटा मोटर्स के ग्रुप सीएफओ पी बी बालाजी ने बताया, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में जेएलआर का दूसरी लग्जरी कार कंपनियों से अच्छा प्रदर्शन रहा लेकिन चीन में बिक्री घटने और डीस्टॉकिंग और वन टाइम इंपेयरमेंट चार्ज से दिसंबर तिमाही में मुनाफे में गिरावट आई।

अब भड़काऊ व आपत्तिजनक कंटेंट नाबालिगों की नजर से रहेगा दूर, इंस्टाग्राम ने लांच किया नया फीचर

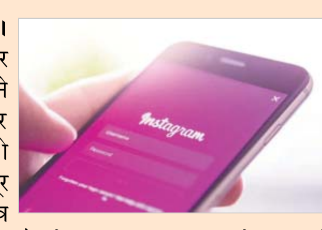

सैन फ्रांसिस्को। इंस्टाग्राम ने प्लेटफॉर्म पर खुद को नुकसान पहुंचाने वाली, भड़काऊ और आपत्तिजनक कंटेंट को नाबालिगों की नजरों से दूर रखने के लिए सेंसिटिव स्क्रीन फीचर लांच किया है जो आपत्तिजनक तस्वीरों, वीडियो-थंबनेल्स को ब्लर रखेगा जबतक यूजर उस पर क्लिक नहीं करता। रिपोर्ट के अनुसा, भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्ध हो चुका यह नया फीचर काटने और खुद को नुकसान पहुंचाने की ऐसी तस्वीरों को ब्लॉक कर देता है जो सर्च, रिकमेंड करने या हैशटैग में अचानक नजर आ सकती हैं और नाबालिगों को शारीरिक नुकसान दे सकती हैं। इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मूसेरी ने द टेलीग्राफ को लिखे एक पत्र में सेंसिटिव स्क्रीन्स के शुरू करने की घोषणा करते हुए एक ब्रिटिश किशोरी की आत्महत्या पर दुख प्रकट किया जिसके परिजनों ने फोटो शेयरिंग एप पर अपनी बेटी को खुद को नुकसान पहुंचाने और अत्महत्या वाले कंटेंट दिखाने का आरोप लगाया था। मूसेरी ने कहा, हम अभी तक वहां नहीं हैं जहां से हमें आत्महत्या या खुद को हानि पहुंचाने वाले मुद्दों पर आने की जरूरत है। हमें वह सब करना है जो हम अपने एप को यूज करने वाले महत्वपूर्ण लोगों के लिए कर सकते हैं। यह घोषणा इंग्लैंड के स्वास्थ्य सचिव मैट हैंकॉक के इंस्टाग्राम की स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक को अपने एप्स और फेस लीगल कार्रवाई पर युवाओं की सुरक्षा बेहतर करने की चेतावनी देने के बाद आई है।

आयकर विभाग जल्द तय करेगा, किस प्रकार के स्टार्टअप को मिलेगी एंजल कर की छूट

नई दिल्ली। आयकर विभाग जल्द इस बात का फैसला करेगा कि किस प्रकार के स्टार्टअप को एंजल कर से छूट मिलेगी। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि उन्हें स्टार्टअप्स से उन्हें एंजल कर से छूट देने संबंधी कई प्रस्ताव मिले हैं। चंद्रा ने कहा कि जल्द हम इन सुझावों के आधार पर इसका समाधान ढूंढ लेंगे। हमें यह तय करना होगा कि कौन-से स्टार्ट अप वास्तविक स्टार्टअप्स हैं और कैसे उन्हें आयकर कानून की धारा 56 (2) से छूट दी जा सकती है। चंद्रा ने कहा कि पहले भी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को धारा (2) से छूट थी और जिन स्टार्ट अप्स को इसको लेकर नोटिस भेजा गया है उनपर स्थगन आदेश जारी कर दिए गए थे। पिछले सप्ताह डीपीआईआईटी ने कर अधिकारियों के साथ उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उनके सुझाव सुने थे। यह बैठक इस वजह से बुलाई गई थी कि क्योंकि कई स्टार्टअप्स ने एंजल कोष के निवेश के लिए कर चुकाने को लेकर उन्हें धारा 56(2) के तहत मिले नोटिसों पर चिंता जताई थी। पिछले महीने सरकार ने स्टार्टअप के लिए एंजल कोष पर आयकर छूट लेने की प्रक्रिया को सुगम किया था और इस तरह के आवेदनों पर निर्णय करने की समयसीमा 45 दिन तय की थी।

संक्षिप्त समाचार

आम चुनावों से पहले फेसबुक का बड़ा कदम, विज्ञापन पारदर्शिता के लिए किया बदलाव

नई दिल्ली। भारत में आगामी आम चुनावों से पहले फेसबुक पर राजनीतिक विज्ञापनों में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कंपनी ने गुरुवार को टूल लांच किया जो इसके यूजर को विशेष राजनीतिक विज्ञापन डालने वाले व्यक्ति और इस पर खर्च की गई रकम की जानकारी उपलब्ध कराएगा। फेसबुक ने कहा कि गुरुवार को शुरू हुए इस टूल से राजनीतिक विज्ञापनों को पब्लिश्ड बाई और पेड फॉर बाई जैसे डिस्क्लेमर्स के साथ देख सकेंगे। डिस्क्लेमर के लिए अधिकृत विज्ञापन दाता विज्ञापन के लिए अपना नाम, उनके द्वारा संचालित पेज या अन्य संस्था का नाम बता सकते हैं। अगर वे किसी अन्य संस्था का नाम लेते हैं तो फेसबुक उससे फोन नंबर, ईमेल और वेबसाइट या भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिए गए मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति प्रमाण पत्र जैसी अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है। फेसबुक के भारत में पब्लिक पॉलिसी के निदेशक शिवनाथ ठुकराल ने कहा, यह संगठन की प्रमाणिकता जांचने के लिए किया गया है। फेसबुक ने पहले इस योजना की घोषणा पिछले साल दिसंबर में की थी जब विज्ञापनदाता राजनीतिक विज्ञापन चलाने के लिए अपनी पहचान और लोकेशन की पुष्टि मोबाइल पर करने में सक्षम थे। फेसबुक ने कहा कि जहां ये प्रक्रियाएं विज्ञापनदाताओं के लिए अभी भी स्वैच्छिक हैं, नए फीचर्स 21 फरवरी से लागू होंगे। जब कोई व्यक्ति डिस्क्लेमर पर क्लिक करता है तो वे सर्च की जाने वाली विज्ञापन लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं जहां वे विज्ञापन निर्माण, शुरुआत और समाप्ति तारीख और प्रदर्शन डाटा जिसमें इंप्रेशंस, स्पेंड की रेंज तथा विज्ञापन देखने वालों की जानकारी देख सकते हैं। फेसबुक ने कहा कि डिस्क्लेमर क्रेडेंशियल्स में भी विज्ञापन लाइब्रेरी दिखेगी।

कच्चे तेल में नरमी से रुपये को मिला सपोर्ट

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में नरमी आने से डॉलर के मुकाबले रुपये में शुक्रवार को भी मजबूती बनी रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 71.36 पर बना हुआ था। इससे पहले सत्र की शुरुआत में पिछले सत्र से सात पैसे की बढ़त के साथ डॉलर के मुकाबले रुपया 71.38 पर खुला। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट को 0.25 आधार अंक घटा कर 6.25 फीसदी किए जाने के फैसले के बाद गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे की मजबूती के साथ 71.45 पर बंद हुआ था। उधर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुस्ती छाने की आशंकाओं से सुरक्षित निवेश के उपकरण के रूप डॉलर की मांग बढ़ने से डॉलर इंडेक्स तकरीबन दो सप्ताह की उंचाई पर आ गया है। पिछले सत्र के मुकाबले 0.07 फीसदी की तेजी के साथ डॉलर इंडेक्स 96.36 पर बना हुआ था। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव दूर करने के संबंध में बातचीत को लेकर असमंजस से भी डॉलर को सपोर्ट मिला है।

सॉफ्टबैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग की अनुषंगी में 2,800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी

नई दिल्ली। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने शुक्रवार को जानकारी दी कि जापान की सॉफ्टबैंक उसकी अनुषंगी ओकनार्थ में 2,800 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी का निवेश करेगी। ओकनार्थ ब्रिटेन में सक्रिय एक वाणिज्यिक बैंक है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने नियामक को दी गई जानकारी में कहा है, इस निवेश के साथ बैंक की इक्विटी पूंजी 7,000 करोड़ रुपए हो जाएगी।' इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने कहा कि ओकनार्थ यूरोप में सबसे तेजी से बढ़ता बैंक है जो बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है।

दिल्लीः खराब मौसम के कारण 38 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बारिश, ओला वृष्टि और तेज हवाओं के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को विमानों का परिचालन बाधित हुआ और 38 अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू उड़ानों के मार्गों में परिवर्तन किया गया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) के अनुसार आज 23 घरेलू उड़ानों में परिवर्तन किया गया और उन्हें जयपुर, लखनऊ, अमृतसर, वाराणसी और इंदौर हवाई अड्डों पर उतारा गया। इसके अलावा नौ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का भी मार्ग परिवर्तित किया गया। छह उड़ानों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। गौरतलब है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो दिन तक ठंड से राहत मिलने के बाद मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई तथा कई स्थानों पर ओले भी गिरे जिससे ठंड बढ़ गई।

दुल्हन की तरह सजा श्याम मंदिर

निशान यात्रा, सुन्दरकाण्ड पाठ, भजन संध्या का आयोजन आज

सूरत, श्रो श्याम सेवा ट्रस्ट द्वारा श्री श्याम मंदिर, सुरतधाम के द्वितीय पाटोत्सव पर आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत आज (शनिवार) से होगी। इस अवसर पर बंगाल की सुप्रसिद्ध कारीगरों द्वारा मंदिर प्रांगण को दुल्हन की तरह सजाया गया है एवं बाबा श्याम, सालासर दरबार एवं शिव परिवार का आलौकिक श्रृंगार किया गया है। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में विशाल पंडाल बनाया गया है और पंडाल में बाबा श्याम का भव्य एवं आलौकिक राजदरबार सजाया गया है

आयोजन की शुरुआत सुबह 7 :30 बजे से निशान यात्रा के साथ की जायेगी। इस मौके पर घोड़ दौड़ स्थित अग्रवाल समाज भवन में निशानों की पूजा की जाएगी, उसके पश्च ?चात निशान यात्रा रवाना होगी। यात्रा में सैंकड़ो भक्त हाथों में निशान थामें झांकियों, बैंड बाजा के साथ बाबा की जयकार करते हुए घोड़ दौड़ रोड, सिटी-लाइट रोड, न्यूसिटी-लाइट रोड होते हुए श्याम मंदिर जाएगी, जहाँ सभी भक्त बाबा को निशान अर्पण करेंगे। मार्ग में यात्रा का स्वागत जगह-जगह पुष्प-वर्षा और जलपान से किया जायेगा।

आयोजन में संगीतमय सुन्दरकाण्ड पाठ का आयोजन शाम 4 बजे श्री मानस मंडल द्वारा किया जायेगा एवं विशाल भजन संध्या का आयोजन शाम 7 बजे से किया जायेगा। भजन संध्या में स्थानीय गायक कलाकारों के अलावा कोलकाता से आमंत्रित कलाकार विकास रुईया और सौरव शर्मा भजनों की शानदार प्रस्तुति देंगे।

पार्किंग व्यवस्था:- आयोजन में आने वाले भक्तों के वाहनों के लिए ट्रस्ट द्वारा पार्किंग की शानदार व्यवस्था की गयी है। इसके लिए न्यू-सिटी लाइट रोड पर श्याम विला बिल्डिंग के पास दो पार्किंग स्थल और मंदिर के पास मेट्रो स्टेशन के पास अलथान रोड पर एक पार्किंग स्थल बनाया गया है। पार्किंग की सुचारु व्यवस्था के लिए 25 से ज्यादा स्वयंसेवक कार्यकर्ता अपनी सेवा देंगें।

महिलाओं ने रचाई मेहन्दी :- श्याम मंदिर के द्वितीय पाटोत्सव के शुभ अवसर पर श्री श्याम सेवा ट्रस्ट की महिला ट्रस्टी एवं सदस्यों द्वारा शुक्रवार को लखदातार हॉल में हाथों पर मेहंदी रचाई गयी। इस अवसर पर ट्रस्ट की कांता सोनी और राधा अग्रवाल सहित 100 से अधिक महिला कार्यकर्ताओं ने मेहंदी लगाई।

गुजरात में जनवरी से अब तक स्वाइन फ्लू के 111। मामले दर्ज, 51 मौतें

सूरत। शहर समेत राज्यभर में स्वाइन फ्लू ने हाहाकार मचा रखा है। जनवरी से अब तक राज्य में स्वाइन फ्लू के 111। मामले दर्ज हो चुके हैं। जिसमें 51 मरीजों को स्वाइन फ्लू लील गया है। राज्य के ज्यादातर शहरों में प्रति दिन स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। ठंड के साथ स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और इस रोग की वजह से हर दो-तीन लोगों की मौत हो रही है। गुरुवार को वलसाड में एक मरीज की मौत हो गई। 1 जनवरी से अब तक राज्य में स्वाइन फ्लू के 111। मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 51 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में स्वाइन फ्लू ग्रस्त 416 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जबकि 650 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। गुरुवार को राज्य में स्वाइन फ्लू के 80 नए मामले सामने आए हैं। जिसमें अहमदाबाद में 26, वडोदरा में 15, सूरत में 6, बनासकांठा में 5, भावनगर में 4, राजकोट में 3, गांधीनगर में 3, भावनगर में 2, जूनागढ़ में 2, खेडा में 2, सुरेन्द्रनगर में 2, साबरकांठा, अमरेली, राजकोट, कच्छ, मोरबी, भरुच, जामनगर, देवभूमि द्वारका, बोटाद और गिर सोमनाथ में स्वाइन फ्लू के एक-एक मामले दर्ज हुए हैं।

कार और बाइक के बीच दुर्घटना में 2 युवकों की मौत, एक घायल

पंचमहल। कालोल के मलाव चौराहे के निकट कार और मोटर साइकिल के बीच हुई दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई। जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पंचमहल जिले की कालोल के मलाव चौराहे के निकट कार ने मोटर साइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। यह घटना उस समय हुई जब दो युवक काटामइडा गांव में आयोजित रामदेव महाराज के पाटोत्सव में शामिल होकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को एम्बयुलैंस 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। कालोल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

आस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने गए सूरत के युवक की डूबने से मौत

सूरत। सूरत के कतारगाम निवासी राजेश रमणभाई कथीरिया का इकलौता पुत्र साहिल पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था। जहां नेशनल पार्क में पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सूरत के कतारगाम के कोटेश्वरनगर निवासी और कंस्ट्रक्शन व्यवसाय से जुड़े राजेश रमणभाई कथीरिया का पुत्र साहिल 11 महीने पहले आईटी की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था। आईटी के बाद साहिल सिविल इंजीनियर बनना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही साहिल की ऑस्ट्रेलिया में मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित नेशनल पार्क में साहिल घुमने गया था। जहां नहाते समय समय पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया से साहिल का शव सूरत लाकर आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

दाणीलीमडा इलाके में पीने के पानी को लेकर समस्या खडी हो गई है। प्रदुषित पानी के विरोध में स्थानिय लोगों ने मणीनगर झोनल ऑफिस पर प्रदर्शन किया।

सूरत पुलिस आयुक्त ने पबजी गेम के खिलाफ जारी की अधिसूचना

सूरत। सूरत पुलिस आयुक्त ने पबजी गेम के खिलाफ अधिसूचना जारी की है। जिसके मुताबिक सूरत शहर की हद में कोई भी व्यक्ति पबजी गेम नहीं खेल सकेगा। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना आगामी 15 मार्च तक अमल में रहेगी। अधिसूचना का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

पिछले काफी समय से पबजी गेम ने बच्चों और युवाओं को दीवाना बना रखा है। युवा इस गेम के पीछे इस कदर पागल हो चुके हैं कि अपने माता-पिता की बात तक नहीं सुन रहे। पबजी गेम के खिलाफ अनेक शिकायतों के बाद सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है और केन्द्र सरकार से इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कुछ समय पहले ही गुजरात सरकार ने राज्य में पबजी गेम पर प्रतिबंध का ऐलान किया था। बच्चों और युवा वर्ग पर इसके बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए सूरत पुलिस आयुक्त सतीश शर्मा ने पबजी गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है। हांलाकि अपराध की जांच में शामिल एजेंसी और शैक्षिक संशोधनों के लिए इस गेम का उपयोग करनेवाले प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस अधिसूचना का उल्लंघन करनेवाले व्यक्तिके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अधिसूचना में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियां समेत गूगल इंडिया, फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्ट्राग्राम माइक्रोसो ट जैसी कंपनियोंको भी पबजी, ब्ल्यू व्हेल चेलेंज इत्यादि गेम की लिंक यदि उनकी कंपनी के जरिए उपयोग की जाती हैं तो उसे तत्काल हटा देने का आदेश दिया गया है।

सीतलवाड़ व उनके पति को अग्रिम जमानत मिली

अहमदाबाद । गुजरात उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को उनके गैर-सरकारी संगठन सबरंग ट्रस्ट से ज ुड़े १.४ करोड रूपए की कथित अनियमितता के मामले में शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी। अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला ने सीतलवाड़ और आनंद को जांच में सहयोग करने तथा १५ फरवरी को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि अगर दंपति जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो राज्य सरकार उनकी जमानत रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।

रुपाणी ने अक्षयवट व हनुमान मंदिर के दर्शन किए

गुजरात के सीएम रूपाणी ने संगम में डुबकी लगाई

अहमदाबाद । गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को पत्नी के साथ संगम में स्नान किया। विजय रूपाणी गुरुवार की रात कुंभ मेला क्षेत्र में आए। उन्होंने कुंभनगर स्थित टेंट सिटी में रात्रि प्रवास किया। शुक्रवार को अपनी पत्नी के साथ उन्होंने संगम स्नान किया। इसके बाद बांध स्थित लेटे हनुमान मंदिर और अक्षयवट का दर्शन और पूजन उन्होंने किया। रूपाणी अखिल भारतीय श्रीपंच निर्मोही अखाड़ा भी पहुंचे। वहां उनका स्वागत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और वाणी अखाड़े के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास ने किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट की डिजाइन व मॉडल देख चहक पड़े। वे गुरुवार शाम पत्नी अंजलि बेन व प्रवासी भारतीय मित्र चंद्रकांत शुक्ल के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने बाबा का दर्शन व सविधि षोडशोपचार पूजन किया। रूपाणी अखिल भारतीय श्रीपंच निर्मोही अखाड़ा भी पहुंचे। वहां उनका स्वागत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और वाणी अखाड़े के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास ने किया। श्रृंगार गौरी में मत्था टेकने के साथ ज्ञानवापी कूप का जल भी प्रसाद स्वरूप ग्रह किया। बाबा को अर्पित चंदन माथे पर लगाए जाते ही अभिभूत मन से हाथ जोड़ शिखर को प्रणाम कर लिया। परिसर में भ्रमण किया और मंदिर विस्तारीकरण व कॉरिडोर निर्माण के बारे में जिज्ञासा जताई। कमिश्नर दीपक अग्रवाल व परामर्शी कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें कॉरिडोर की डिजाइन व मॉडल दिखाया। इसकी विशिष्टता, जरूरत और श्रद्धालु हित में प्रस्तावित निर्माण के बारे में भी बताया।

एयरपोर्ट से ही साथ रहे न्यास अध्यक्ष आचार्य पं. अशोक द्विवेदी ने उन्हें मंदिर का महात्म्य बताया और मौलि बांधी। कमिश्नर ने दुपट्टा व प्रसाद प्रदान किया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की नैत्यिक सांध्य आरती में पहुंचे गुजरात के सीएम ने वैदिक रीति से गंगा पूजन किया। गंगा आरती की झांकी देखी और सपरिवार तस्वीरें भी खिंचाई। गंगा सेवा निधि के सचिव हनुमान यादव व कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने प्रसाद, रुद्राक्ष की माला व स्मृति चिह्न प्रदान किया।

पाटण में क्लस्टर संमेलन का आयोजन हुआ

आशाबेन कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुई

ऊंझा नगरपालिका के १५ अपक्ष कॉर्पोरेटर भी बीजेपी में शामिल :जो काम मिलेगा उसे निष्ठा से करेगी : आशा

अहमदाबाद । कांग्रेस और विधायक पद से हालही में इस्तीफा दे चुकी आशाबेन पटेल आज शुक्रवार के दिन अधिकारिक रुप से बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में शामिल होने से पहले गुरुवार को आशाबेन ने मुख्यमंत्री नीतिन पटले से मुलाकात की थी। उन्होंने गांधीनगर स्थित स्वर्णिम संकुल में आकर उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की। आज आशाबेन पाटण में बीजेपी की ओर से तीन लोकसभा सीटो के क्लस्टर संमेलन में शामिल हुई जहां आशाबेन पटेल को विधिवत रुप से बीजेपी में शामिल किया गया। आशाबेन पटेल आज विधिवत रुप से केसरीया धारण करते हुए बीज ेपी में शामिल हो गई। उनके साथ उंझा नगरपालिका के १५ अपक्ष कोर्पोरेटर, एक कांग्रेसी कॉर्पोरेटर और तालुका पंचायत के १० अपक्ष सदस्य समेत ११०० कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के नेताओ ने आशाबेन का भव्य स्वागत किया।

पाटण में क्लस्टर संमेलन में कार्यकरो ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पर चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल का मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण गिना जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने से पहले गुरुवार को आशाबेन ने मुख्यमंत्री नीतिन पटले से मुलाकात की थी। उन्होंने गांधीनगर स्थित स्वर्णिम संकुल में आकर उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की। आज आशाबेन पाटण में बीजेपी की ओर से तीन लोकसभा सीटो के क्लस्टर संमेलन में शामिल हुई जहां आशाबेन पटेल को विधिवत रुप से बीजेपी में शामिल किया गया। क्लस्टर संमेलन में वरिष्ठ बीजेपी नेता हाजिर रहे। पूर्व विधायक, शक्ति केन्द्रो के प्रमुख भी उपस्थित रहे। पाटण में क्लस्टर संमेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर भी उपस्थित रहे। उन्हीं के नेतृत्व में इसका आयोजन हुआ था।

उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल भी उपस्थित रहे। ऊंझा कांग्रेस के विधायक आशाबेन पटेल विधिवत रुप से बीजेपी में शामिल हुए। उनके साथ ११०० से भी अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद आशाबेन पटेल ने कहा कि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हे जो काम मिलेगा वह काम पुरी इमानदारी से करेगी। निष्ठापूर्वक काम करने की बात आशाबेन पटेल ने की है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)**